देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित

www.page3news.in

नगर संस्करण वर्ष 16 अंकः 111 पृष्ठ : 8 मूल्यः एक रूपए

विचार-प्रवाह...ब्लैक फंगस के रूप में नई चुनौती

पेज थ्री

देहरादून, शुक्रवार, 30 जुलाई 2021

मौसम अधिकतम 29.0° न्यूनतम 24.0° | 42243.40 | 2 तालिबान का प्रवक्ता नही है पाकिस्तान | 7 मेरी कॉम को ओलिंपिक सपना टूटा

नई शिक्षा नीति भाग्य बदलने वाली

प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक साल पूरा होने पर राष्ट्र को किया संबोधित

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के 'महायज्ञ' में बड़े तत्वों में से एक है और यह युवाओं को विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट', क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश सहित शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी की।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र से जुड़े देश भर के नीति निर्माता, छात्र और शिक्षक भी शामिल हुए।

पढ़ाई के लिए विदेशों से भारत आये छात्र

"नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है।" उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का युवा अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, वह मौका चाहता है और पुराने बंधनों व पिंजरों से मुक्ति चाहता है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री।

पाकिस्तानी ISI कर सकती है हिंसा भड़काने की साजिश

पीएम ने कहा, "आज शुरु हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी।"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और 34 वर्षीय पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लाई गई है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे समय में आयी है जब देश आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोतसव मना रहा है और एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियानवयन आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बन गया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में संबंधित हितधारकों ने बहुत मेहनत की है।

उन्होंने कहा, "भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में, यानि आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें हम कैसी दिशा दे रहे हैं। मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े कारकों में से एक है।" उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को पिछले साल 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

पीएम ने इन अन्य पहलों की शुरुआत की

प्रधानमंत्री ने जिन अन्य पहलों की शुरुआत की उनमें ग्रेड 1 के छात्रों के लिए तीन महीने का नाटक आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल "विद्या प्रवेश", माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए एकीकृत कार्यक्रम निष्ठा 2.0, सफल (सीखने के स्तर के विश्लेषण के लिए संरचित मूल्यांकन), सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा और पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित एक वेबसाइट शामिल हैं।

संक्षिप्त समाचार

सैन्य कार्रवाई से नहीं निकल सकता अफगानिस्तान की स्थिति का हल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति का हल सैन्य कार्रवाई से नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बहुत विस्तृत चर्चा हुई और वो दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बातचीत के जरिए राजनीतिक हल निकालने पर जोर दिया है।

दिल्ली विस ने सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने के लिए पारित किया प्रस्ताव

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया।

मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में ओबीसी और ईडब्लूएस छात्रों को मिलेगा आरक्षण

पीएम मोदी ने किया ट्वीट, इससे हर साल हजारों युवाओं को फायदा होगा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर कर लिया है। अब दोनों ग्रेजुएट (एमबीबीएस, बीडीएस), पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

हर साल 5000 से ज्यादा छात्रों को होगा लाभः इस फैसले से करीब 5550 छात्रों को लाभ होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पिछड़ा और ईडब्लूएस वर्ग दोनों के लिए उचित आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल डठठै में करीब 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स और पोस्टग्रेजुएट में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है। इसी तरह डठठै में करीब 550 EWS छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 EWS छात्रों को लाभ हो सकता है।

यह व्यवस्था ऑल इंडिया कोटे के तहत यूजी और पीजी मेडिकलध्डेंटल कोर्सेज (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/ बीडीएस/ MD) के लिए मौजूदा अकादमिक सत्र 2021–22 से लागू होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने मेडिकल कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत आरक्षण का फैसला किया है। इससे हर साल हमारे हजारों युवाओं को लाभ होगा। काफी समय से इसको लेकर सरकार से मांग हो रही थी।

दो दिन पहले पीएम ने की थी समीक्षा

दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा की थी। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों को इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया था। सोमवार को बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानून एवं न्याय और समाज कल्याण सचिवों के साथ–साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए और कोटा के मुद्दे पर चर्चा की गई।

देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल देखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 43,509 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 640 लोगों की इस दौरान कोरोना के चलते मौत हो गई। कोरोना से कुल मौतों की संख्या 4,22,662 हो गई है। केरल में कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केरल में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के नए मामले 20,000 को पार कर गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या एक बार फिर चार लाख के आंकड़े को पार करते हुए 4,03,840 हो गई है। देश में कोरोना की रिकवरी दर 97.38 फीसद हो गई है।

सरकार के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 38,465 लोगों को अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से छुट्टी दे दी गई, जिससे अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या तीन करोड़ से ज्यादा (3,07,01,612) हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अब तक कुल 45.07 करोड़ (45,07,06,257) कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 43,92,697 वैक्सीन की खुराक शामिल हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को अब तक 15.38 करोड़ से अधिक खुराक लगाए जा चुके हैं।

इस बीच देश में कोरोना की तेजी से टेस्टिंग की जा रही है। 28 जुलाई तक कोरोना की 46.26 करोड़ से ज्यादा (46,26,29,773) टेस्टिंग की जा चुकी है, जिसमें बुधवार को 17,28,795 कोरोना की टेस्टिंग की गई है। केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण शनिवार और रविवार (31 जुलाई और 1 अगस्त) को पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है।

चिंता

■कोविड प्रबंधन को लेकर केरल भेजी गई केंद्रीय टीम

भारत 51 टाइगर रेसेर्वेस का घर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वाइल्डलाइफ से जुडे लोगों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने की देश की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर, वन्यजीव प्रेमियों, विशेष रूप से बाघ संरक्षण के प्रति उत्साही लोगों को बधाई। विश्व स्तर पर बाघों की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी का घर, हम अपने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल इकोसिस्टम को पोषित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। बता दें कि भारत में अब दुनिया भर में रहने वाले बाघों की कुल संख्या का लगभग 70 प्रतिशत बाघ रहते हैं।

पीएम मोदी ने वाइल्डलाइफ प्रेमियों को दी बधाई

पीएम मोदी ने आगे ट्वीट करते हुए कहा, भारत 18 राज्यों में फैले 51 टाइगर रेसेर्वेस का घर है। 2018 की अंतिम बाघ गणना में बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के समय से 4 साल पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया।